permanent absorption basis, his service conditions are governed by the terms as spelt out in the offer or as decided by the PSU.

Ministry of Defence has received no complaints/representations from such officers about their early retirement by the PSUs.

गढ़वाल क्षेत्र में पनधारा-विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना

*548. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पनधारा-विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कोई परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च हो रही है;

(ग) क्या इस परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कोई समालोचनात्मक समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा ऐसी कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Construction of Super Highways in Delhi

*549. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whehter Government propose to construct Super Highways in Delhi;

(b) if so, the length of the Highways and the extent to which the same would ease the traffic congestion on Delhi roads;

(c) the extent of forest area likely to be covered in the Highways; and

(d) whether environmentalists have expressed serious reservations about the proposed Highways; if so, whether the Super Highways have the approval of Ministry of Environment and Forests?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) The Govt. of National Capital Territory of Delhi (NCTD) have a proposal for an urban expressway (Ring Expressway) about 80 kms in length linking the National Highways No. 1, 10, 8 and 2 in Delhi. The alignment of the expressway has not yet been finalised. As such the extent of forest area likely to be covered in the proposed Expressway/Super Highway cannot be indicated at this stage.

(d) Yes, Sir. However environmental clearance will be obtained by NCTD after alignment has been finalised.

The Central Government is responsible for the development and maintenance of National Highways only. The proposed expressway does not form part of the National Highway network and hence is the responsibility of Government of National Capital Territory of Delhi.

नए सैनिक स्कूलों का खोला जाना

*550. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खोले गए सैनिक स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में एक भी सैनिक स्कूल नहीं खोला गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार मालवा क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोलने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (ङ) संलग्न विवरण के अनुसार, देश के प्रत्येक बड़े प्रदेश में एक सैनिक स्कूल है (नीचे देखिए)। इस तरह पूरे देश में कुल 18 सैनिक स्कूल हैं। मध्य प्रदेश में भी रीवा जिले में एक सैनिक स्कूल है। 1978 के बाद देश में न तो कोई नया सैनिक स्कूल खोला गया है,